Toppersnotes®
Unleash the topper in you

UPSC – CSE

सिविल सेवा परीक्षा

संघ लोक सेवा आयोग

सामान्य अध्ययन

पेपर 3 – भाग – 1

भारतीय अर्थव्यवस्था

SIERRA INNOVATIONS

IAS

पेपर - 3 भाग - 1

भारतीय अर्थव्यवस्था

S.No.	Chapter Name	Page No.
1.	**भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास** • ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था • ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था • स्वतंत्रता के बाद की अर्थव्यवस्था • नियोजित और मिश्रित अर्थव्यवस्था	1
2.	**अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत** • सूक्ष्म और स्थूल अर्थव्यवस्था • आर्थिक प्रणाली ○ विभिन्न आर्थिक प्रणालियाँ ○ पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में अंतर • अर्थव्यवस्था के क्षेत्र • माँग आपूर्ति प्रबंधन • आपूर्ति क्या है? ○ आपूर्ति के निर्धारक ○ आपूर्ति की लोच • बाजार संतुलन • मांग और आपूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव	5
3.	**राष्ट्रीय आय** • राष्ट्रीय आय के पहलू ○ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ○ शुद्ध घरेलू उत्पाद(NDP) ○ सकल राष्ट्रीय उत्पाद(GNP) ○ सकल राष्ट्रीय उत्पाद(NNP) • राष्ट्रीय आय की गणना करने के तरीके • आर्थिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति	12
4.	**धन और पैसे की आपूर्ति** • धन का विकास • धन के कार्य • धन का वर्गीकरण • धन के प्रकार • क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन • मुद्रा आपूर्ति और मौद्रिक समुच्चय ○ मुद्रा बाजार ○ संगठित क्षेत्र	18

	○ असंगठित क्षेत्र ○ धन की आपूर्ति ○ धन गुणक ○ मौद्रिक समुच्चय • वित्तीय प्रणाली • राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन	
5.	**मौद्रिक नीति** • मात्रात्मक उपकरण ○ खुला बाजार संचालन (Open Market Operations - OMO) ○ बाज़ार स्थिरीकरण योजना • गुणात्मक उपकरण • मौद्रिक नीति समिति ○ उर्जित पटेल समिति	**27**
6.	**भारत में बैंकिंग** • वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण ○ राष्ट्रीयकरण का चरण (1969-1991) ○ राष्ट्रीयकरण करने के कारण (1969) • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ○ RBI के मुख्य कार्य ○ भारतीय रिजर्व बैंक की आय और व्यय के स्रोत ○ भारतीय रिजर्व बैंक के भंडार और अधिशेष पूंजी ○ भारतीय रिजर्व बैंक की न्यूनतम रिजर्व प्रणाली ○ भारतीय रिजर्व बैंक की संपत्ति और देनदारियां ○ लोकपाल योजना - RBI शिकायत निवारण तंत्र ○ बिमल जालान समिति • भारत में बैंकों का विभाजन ○ अनुसूचित बैंक ○ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ○ सहकारी बैंक ○ गैर अनुसूचित बैंक • विशिष्ट बैंक ○ विभेदित बैंक ○ डेवलपमेंट बैंक • गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFC) • NBFC के रूप में पंजीकरण करने की शर्तें • बैंकिंग क्षेत्र में सुधार ○ नरसिम्हम समिति-द्वितीय (1998) ○ नचिकेत मोर समिति (2013) ○ पीजे नायक समिति (2014) ○ बेसल मानदंड • दिवाला और दिवालियापन • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार के लिए मिशन इंद्रधनुष	**34**

	• वित्तीय समावेशन ○ वित्तीय समावेशन की आवश्यकता ○ भारत में वित्तीय समावेशन की चुनौतियां ○ सरकार के उपाय ○ डिजिटल वित्तीय समावेशन (DFI) ○ चुनौतियां ○ मांग पक्ष का अंतर ○ असफल कृषि तकनीक ○ औपचारिक वित्त तक पहुंचने में MSME की अक्षमता ○ डिजिटल कॉमर्स में विश्वास और सुरक्षा ○ डिजिटल रूप से सुलभ ट्रांजिट सिस्टम ○ भारत में की गई डिजिटल वित्तीय समावेशन पहल • स्वर्ण निवेश योजनाएं	
7.	**मुद्रास्फीति और व्यापार चक्र** • मुद्रास्फीति के कारण ○ अन्य कारक • मुद्रास्फीति के प्रकार ○ मुख्य मुद्रास्फीति बनाम शीर्षक मुद्रास्फीति ○ मुद्रास्फीति की जांच के उपाय • WPI बनाम CPI • उत्पादक मूल्य सूचकांक(PPI) • आवास मूल्य सूचकांक • सेवा मूल्य सूचकांक (SPI) • मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण • मुद्रास्फीति के प्रभाव ○ अन्य महत्वपूर्ण शर्तें • व्यापारिक चक्र • आर्थिक सुधार • आर्थिक सुधार का आकार	**63**
8.	**भारत में बेरोजगारी** • भारत में बेरोजगारी का उपाय • भारत में बेरोज़गारी के प्रकार • भारत में बेरोज़गारी के कारण • बेरोज़गारी का प्रभाव • सरकार की पहल ○ जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ○ ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण (TRYSEM) ○ ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ○ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) ○ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) ○ सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)	**75**
9.	**गरीबी** • गरीबी के प्रकार	**81**

	○ लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक • भारत में गरीबी का आकलन • गरीबी के आकलन के लिए विभिन्न समितियों की अनुशंसाएं • रंगराजन समिति ○ गरीबी से संबंधित शर्तें • भारत में गरीबी के कारण ○ गरीबी का जाल • भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम • बहुआयामी निर्धनता सूचकांक	
10.	**भारत में वित्तीय बाज़ार** • मुद्रा बाजार ○ भारत में मुद्रा बाजार के अवयव ○ संगठित क्षेत्र ○ असंगठित क्षेत्र ○ म्यूचुअल फंड्स ○ एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) ○ डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड ○ पूंजी बाजार ○ परियोजना वित्तपोषण ○ वित्तीय संस्थाएं ○ विशिष्ट वित्तीय संस्थान (SFI) ○ सम्बंधित उद्योग • वित्तीय विनियमन ○ नियामक संस्थाएं ○ पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ○ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ○ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ○ अर्ध-विनियामक एजेंसियां • विभिन्न नियामक • केन्द्रीय मंत्रालय • कुछ वित्तीय मध्यस्थों के लिए विशेष क़ानून	**87**
11.	**भारत में प्रतिभूति बाजार** • प्राथमिक और द्वितीयक बाजार • शेयर बाजार • राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज • स्टॉक एक्सचेंजों में खिलाड़ी • भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (सेबी) • उत्पाद व्यवसाय • स्पॉट एक्सचेंज • शेयर बाजार की महत्वपूर्ण शब्दावली • विदेशी वित्तीय निवेश ○ एफएफआई के प्रकार	**96**

	○ अन्य संबंधित शर्तें • सहभागी नोट (पी-नोट्स, या पीएन) • बचाव निधि(Hedge Fund) • क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप (CDS) • प्रतिभूतिकरण(Securitization) • भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड • गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स • केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम- एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (सीपीएसई ईटीएफ) • पेंशन क्षेत्र में सुधार • अचल संपत्ति और बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट	
12.	**बाहरी क्षेत्र और भुगतान संतुलन** • महत्वपूर्ण परिभाषाएं • भुगतान का संतुलन ○ चालू खाता बनाम पूंजी खाता • मुद्रा प्रकार ○ विशेष आर्थिक क्षेत्र(SEZ) • विदेशी निवेश • बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) • व्यापार संवर्धन • निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं • विदेश व्यापार नीति के तहत प्रमुख पहल • नई विदेश व्यापार नीति 2021-2026 • बैंकिंग पूंजी लेनदेन • मुद्रा परिवर्तनीयता • विदेशी कर्ज • भारत में विनिमय दर प्रबंधन • व्यापार संतुलन	**110**
13.	**अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान** • अंतरराष्ट्रीय संगठन ○ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ○ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ○ विश्व बैंक ○ अन्य वस्तु व्यापार समझौते ○ भारत और विश्व व्यापार संगठन ○ एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ○ एशियाई विकास बैंक ○ आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)	**129**
14.	**भारतीय सार्वजनिक वित्त** • सार्वजनिक राजस्व • सरकारी व्यय • सार्वजनिक ऋण ○ सार्वजनिक ऋण की संरचना • राजकोषीय नीति	**146**

	• राजकोषीय नीति बनाम मौद्रिक नीति
	  ○ राजकोषीय नीति के प्रकार
	  ○ विकास
	• घाटा
	  ○ घाटे के प्रकार
	• राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के उपाय
	  ○ भारत में राजकोषीय समेकन
	  ○ FRBM अधिनियम, 2003
	• सार्वजनिक ऋण
	  ○ राज्यों को केंद्रीय स्थानांतरण
	  ○ राज्य वित्त	

15.	**बजट बनाना**
	• वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
	  ○ बजट के प्रकार
	  ○ बजट घटक
	  ○ प्राप्तियां
	  ○ व्यय
	  ○ विकासात्मक और गैर-विकासात्मक व्यय
	  ○ योजनागत और गैर-योजनागत व्यय
	  ○ बजट में डेटा
	• बजट के अधिनियमन की प्रक्रिया
	  ○ बजट 2021
	• कोविड टीकाकरण : वित्त वर्ष 22 में ₹35000 करोड़ खर्च करना।
	• भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा:
	  ○ आर्थिक सर्वेक्षण 2021
	• सरकारी खाते
	• घाटा वित्तपोषण
	  ○ घाटे के वित्तपोषण की आवश्यकता
	  ○ घाटे के वित्तपोषण के साधन
		157

16.	**कराधान**
	• कराधान के पीछे उद्देश्य
	• कराधान के तरीके
	• कर के प्रकार
	  ○ प्रत्यक्ष कर
	  ○ केंद्र द्वारा लगाया गया प्रत्यक्ष कर
	  ○ राज्यों द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष कर
	  ○ अप्रत्यक्ष कर
	  ○ GST के बाद केंद्र द्वारा लगाया गया अप्रत्यक्ष कर
	  ○ वस्तु एवं सेवा कर
	  ○ अन्य महत्वपूर्ण पहलू
	  ○ केंद्र द्वारा लगाए गए अन्य अप्रत्यक्ष कर
	  ○ राज्यों द्वारा लगाया गया अप्रत्यक्ष कर
		163

	• कर सुधार ○ प्रत्यक्ष कर सुधार • राजा चेलिया समिति (1990 के दशक के प्रारंभ में) • केंद्र से राज्यों को फंड ट्रांसफर ○ वित्त आयोग अनुदान ○ राज्यों को अन्य स्थानान्तरण • कराधान में महत्वपूर्ण शर्तें ○ लाफ़र वक्र ○ अंतर्राष्ट्रीय कर संधियाँ	
17.	**अनुदान** • कृषि अनुदान की आवश्यकता • अनुदानों का वर्गीकरण ○ प्रत्यक्ष अनुदान ○ अप्रत्यक्ष कृषि अनुदान ○ कृषि अनुदान के लाभ और मुद्दे • संवितरण के विभिन्न तरीके • भारतीय खाद्य निगम (FCI) • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 • विश्व व्यापार संगठन और कृषि अनुदान	**182**
18.	**बुनियादी ढाँचा** • अवसंरचना विकास ○ बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित मुद्दे • उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) योजना। • व्यवहार्यता गैप फंडिंग (VGF) • सड़कें • भारतमाला परियोजना • रेलवे ○ रेलवे सुधारों पर विवेक देबरॉय समिति ○ समर्पित माल ढुलाई गलियारे • बंदरगाह ○ सागरमाला ○ तटीय आर्थिक क्षेत्र (CEZs) • हवाई अड्डे ○ UDAN-क्षेत्रीय संपर्क योजना • औद्योगिक गलियारे ○ 5 औद्योगिक गलियारा • विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) • मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क • इसका राष्ट्रीय राजमार्ग 17, ब्रह्मपुत्र पर प्रस्तावित जोगीघोपा जलमार्ग टर्मिनल, नवनिर्मित रूपसी और गुवाहाटी हवाई अड्डों के साथ-साथ मुख्य रेलवे मार्ग से सीधा संपर्क होगा। • बिजली क्षेत्र ○ सौर ऊर्जा • तेल और गैस क्षेत्र	**188**

	○ सामरिक पेट्रोलियम भंडार ○ भारतीय गैस विनिमय • ऊर्जा सुरक्षा ○ जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 • जैव ईंधन ○ इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम • स्मार्ट सिटी, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) और सभी के लिए आवास • सभी के लिए आवास • एनआईआईएफ (राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष) • राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन	
19.	**निवेश मॉडल** • स्रोत • निवेश मॉडल के प्रकार ○ भारत द्वारा उपयोग किए जाने वाले निवेश मॉडल	**209**
20.	**उद्योग** • 1991 से पहले की औद्योगिक नीति • औद्योगिक नीति संकल्प, 1948 • औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 • नवरत्न, महारत्न और मिनीरत्न • औद्योगिक नीति वक्तव्य, 1977 • औद्योगिक नीति वक्तव्य, 1980 • 1991 के बाद की औद्योगिक नीति • उद्योग पर LPG सुधारों का प्रभाव • राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011 • विनिवेश के प्रकार • व्यापार सुगमता ○ मेक इन इंडिया • औद्योगिक विकास के चरण • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) • सीमित देयता भागीदारी (LLP) अधिनियम, 2008: • खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) • क्षेत्रीय चिंताएं • स्टार्ट-अप इंडिया	**212**
21.	**आपूर्ति श्रृंखला और खाद्य प्रसंस्करण** • खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (FPI) • आपूर्ति श्रृंखला योजनाएं • आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना • खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)	**230**
22.	**भारत में भूमि सुधार** • भूमि सुधार के लिए तर्क • भूमि सुधार के घटक	**237**

	• भूमि सुधारों का प्रभाव • भूमि सुधार [स्वतंत्रता से पहले और बाद में] • भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 • भूमि सुधारों के कार्यान्वयन में समस्याएं • सामाजिक प्रभाव आकलन	
23.	**आर्थिक सुधार** • 1991 आर्थिक संकट • 1991 के सुधार • भारत में आर्थिक सुधार • सुधार के उपाय • आर्थिक सुधारों की पीढ़ी • मिश्रित अर्थव्यवस्था	**246**
24.	**भारत में योजना** • स्थानीय योजना • राष्ट्रीय योजना • योजना के प्रकार • योजना के प्रमुख उद्देश्य • भारत में योजना का विकास • राष्ट्रीय विकास परिषद • पंचवर्षीय योजनाएं • NITI (नीति) आयोग	**254**
25.	**बीमा** • पृष्ठभूमि • भारतीय जीवन बीमा निगम (LICI) • भारतीय सामान्य बीमा निगम (GIC) • भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (AICIL) • बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA)। • पुनर्बीमा • जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम • क्रेडिट गारंटी फंड • एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECGC) • राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (NEIA) • बीमा प्रवेश और सघनता • नीतिगत पहल ○ नई सुधार पहल • नई बीमा योजनाएं	**265**
26.	**वृद्धि, विकास और खुशहाली** • आर्थिक संवृद्धि • आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक ○ आर्थिक कारक ○ गैर-आर्थिक कारक • आर्थिक विकास ○ आर्थिक संवृद्धि और विकास के बीच अंतर	**273**

	• असमानता
	• सांख्यिकी
	  ○ लिंग असमानता सूचकांक
	• खुशहाली
	  ○ नज और सार्वजनिक नीति
	• समावेशी वृद्धि और संबंधित मुद्दे
	  ○ भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता
	• भारत में निर्धनता आकलन
	• जनसांख्यिकीय विभाजन
	• भारत में श्रम कानून
	  ○ प्रवासी श्रमिक
	• औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था
	• सतत विकास लक्ष्य (SDGs)
	• सतत विकास के तत्व	

27.	**कृषि**
	• पंचवर्षीय योजनाओं के तहत कृषि का विकास
	• कृषि एवं हरित क्रांति
	  ○ हरित क्रांति पूर्व चरण (1951-68)
	  ○ हरित क्रांति का प्रारंभिक चरण (1968-81)
	  ○ बाद में हरित क्रांति का चरण (1987-92)
	  ○ हरित क्रांति के प्रभाव
	• भूमि उपयोग से संबंधित शर्तें
	• भूमि उपयोग से संबंधित शर्तें
	• कृषि विपणन
	• सार्वजनिक वितरण प्रणाली
	• निवेश प्रबंधन योजनाएं/मिशन
	• जल प्रबंधन-सूक्ष्म सिंचाई
	• त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
	• कृषि साख
	• खाद्य सुरक्षा
	• उत्पादन प्रबंधन योजनाएं
	• न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)
	• प्रधानमंत्री आशा (प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान)
	• उत्पादन प्रबंधन योजनाएँ
	  ○ कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन अधिनियम 2017
	• आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
	• कृषि निर्यात नीति 2018
	• मूल्य स्थिरीकरण के उपाय
	• कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर
	• कृषि में विस्तार प्रबंधन
	• कृषि विस्तार के लिए जनसंचार माध्यमों का समर्थन
	• संबद्ध गतिविधियों का प्रबंधन-अतिरिक्त आय अर्जित करना
		290

	○ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Rkvy) ○ कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और बनाए रखना (ICAR-ARYA) ○ पहले किसान (आईसीएआर) ○ पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना (ICAR) ○ दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (DDU-GKY) ○ दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ○ महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) ○ नई रोशनी योजना ○ प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)	

1 CHAPTER भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास

स्वतंत्रता पूर्व अवधि	• उत्पादन या उत्पादकता स्तरों की संरचना में थोड़े से बदलाव के साथ, लगभग ठहराव की अवधि।
1930 के दशक के मध्य	• राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी जिन्होंने भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता को देखा। • भारत एक विदेशी देश, यूनाइटेड किंगडम के लाभ के लिए विकास का अनुसरण कर रहा था।
स्वतंत्रतापूर्व संध्या पर भारत की आर्थिक रूपरेखा	• औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का एक उत्कृष्ट परिदृश्य पूरी तरह अस्त-व्यस्त था। • कृषि और विनिर्माण दोनों में मूलभूत समस्याएँ थीं, जिसमें सरकार केवल एक न्यूनतम भूमिका निभा रही थी।

ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था

- **प्रकार:** स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी।
- **कृषि:** अधिकांश लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत
  - विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियों की विशेषता वाली अर्थव्यवस्था।
  - **उदाहरण:** सूती और रेशमी वस्त्रों के क्षेत्र में हस्तशिल्प उद्योग।
  - धातु और कीमती पत्थर के काम आदि।
- **बंगाल:** वस्त्र उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध - मलमल का कपड़ा
- भारतीय उत्पादों में इस्तेमाल की गई सामग्री की अच्छी गुणवत्ता और यहाँ से अधिकांश आयातों में देखे जाने वाले शिल्प कौशल के उच्च मानकों के लिए दुनिया भर में प्रतिष्ठा मिली।

ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था

कृषि क्षेत्र	• अर्थव्यवस्था का प्रकार: मूल रूप से कृषि प्रधान
	• लोगों की भागीदारी: देश की लगभग 85% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से आजीविका प्राप्त करती थी।
	• कृषि उत्पादकता कम हो गई, खेती के तहत कुल क्षेत्र के विस्तार के कारण इस क्षेत्र में कुछ वृद्धि हुई।
	• कृषि क्षेत्र में स्थिरता के कारण
	  ○ अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई भूमि बंदोबस्त प्रणाली: बंगाल में लागू की गई ज़मींदारी प्रणाली ने कृषि क्षेत्र से होने वाले लाभ को काश्तकारों के बजाय जमींदारों को दे दिया।
	  ○ प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर।
	  ○ सिंचाई की सुविधा का अभाव।
	  ○ उर्वरकों का नगण्य उपयोग।
	• नकदी फसलों की खेती में वृद्धि: कृषि के व्यावसायीकरण के कारण नकदी फसलों की अपेक्षाकृत अधिक उपज।

	• ब्रिटिश नीति का शायद ही कोई उपयोग था क्योंकि खाद्य फसलों के उत्पादन के बजाय, नकदी फसलों का उत्पादन किया गया था, जिनका उपयोग अंततः इंग्लैंड में लगे औद्योगिक कारखानों में किया जाता था। • सिंचाई के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई, लेकिन भारत की कृषि में सीढ़ीदार, बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी और मिट्टी के विलवणीकरण में निवेश की कमी थी।

औद्योगिक क्षेत्र	• औपनिवेशिक शासन में भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार विकसित नहीं कर सका।
	• देश के हस्तशिल्प उद्योगों में गिरावट आई और कोई आधुनिक औद्योगिक आधार विकसित नहीं हो सका।
	• नीति के पीछे ब्रिटेन का उद्देश्य:
	  ○ ब्रिटेन में विकसित होने वाले आधुनिक उद्योगों के लिए भारत को महत्वपूर्ण कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे।
	  ○ उन उद्योगों के तैयार उत्पादों के लिए भारत को एक विशाल बाजार में बदलना ताकि उनका निरंतर विस्तार उनके गृह देश ब्रिटेन के अधिकतम लाभ के लिए सुनिश्चित किया जा सके।
	• नीतियों का प्रभाव
	  ○ हस्तशिल्प उद्योग की गिरावट के कारण भारी बेरोजगारी
	  ○ भारतीय उपभोक्ता बाजार में माँग स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति से वंचित थी जिसके कारण ब्रिटेन से सस्ते विनिर्मित वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई।
	  ○ आधुनिक उद्योग की शुरुआत: उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान, आधुनिक उद्योग ने भारत में जड़ें जमाना शुरू कर दिया लेकिन इसकी प्रगति बहुत धीमी रही।
	  ○ सूती वस्त्र मिलें: भारतीयों का वर्चस्व
	  ■ स्थान: महाराष्ट्र और गुजरात,
	  ○ जूट मिलें: विदेशियों का प्रभुत्व
	  ■ स्थान: बंगाल
	  ○ लौह और इस्पात उद्योग: 20वीं सदी की शुरुआत में आए।
	  ■ 1907: टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को) की स्थापना हुई।
	  ○ अन्य उद्योग: द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद चीनी, सीमेंट, कागज आदि उद्योगों का उदय हुआ।

विदेशी व्यापार	• अंग्रेजों द्वारा उत्पादन, व्यापार और शुल्क की प्रतिबंधात्मक नीतियों ने भारत के विदेशी व्यापार का ढाँचा, संरचना और मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। • अंग्रेजों ने भारत के आयात और निर्यात पर एकाधिकार बनाए रखा। • औपनिवेशिक काल के दौरान बड़े पैमाने पर निर्यात अधिशेष उत्पन्न हुआ था • उनकी नीतियों का प्रभाव: भारत कच्चे उत्पाद रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, जूट आदि जैसे प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक बन गया और ब्रिटिश कारखानों में बनी हल्की मशीनरी व सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसी वस्तुओं का आयातक बनकर रह गया। • स्वेज नहर के खुलने से भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण और तेज हो गया। • निर्यात अधिशेष उत्पादन ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। • कई आवश्यक वस्तुएँ जैसे खाद्यान्न, कपड़े, मिट्टी का तेल आदि की घरेलू बाजार में उपलब्धता कम हो गई। • इसके परिणामस्वरूप भारत में सोने या चाँदी का कोई प्रवाह नहीं हुआ, बल्कि इसका उपयोग ब्रिटेन में औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्थापित एक कार्यालय द्वारा किए गए खर्चों के भुगतान के लिए किया जाता था व अंग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्ध पर खर्च किया जाता था। • इन सब के कारण भारतीय धन की निकासी हुई।

जनसांख्यिकीय दशा	• पहली जनगणना: 1881
	• भारत की जनसंख्या वृद्धि में असमानता थी।
	• 1921 तक भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में था।
	• 1921 के बाद संक्रमण का दूसरा चरण शुरू हुआ।
	• इस स्तर पर न तो भारत की कुल जनसंख्या और न ही जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक थी।
	• सामाजिक विकास संकेतक:
	  ○ समग्र साक्षरता स्तर: 16% से कम
	  ○ महिला साक्षरता स्तर: 7%
	  ○ जनसंख्या के बड़े हिस्से तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था।
	  ○ जल और वायु जनित रोग बड़े पैमाने पर थे।
	  ○ कुल मृत्यु दर बहुत अधिक थी।
	  ○ शिशु मृत्यु दर: 218 प्रति हजार जबकि वर्तमान शिशु मृत्यु दर 33 प्रति हजार है।
	  ○ जीवन प्रत्याशा: 32 वर्ष वर्तमान 69 वर्षों के विपरीत।
	• व्यापक गरीबी: उस समय की भारत की जनसंख्या की दशा और ख़राब हो गई।

व्यावसायिक संरचना	• कृषि क्षेत्र: कार्यबल का सबसे बड़ा हिस्सा 70-75% के उच्च स्तर पर बना रहा। • विनिर्माण क्षेत्र: कार्यबल के 10% हिस्से को रोजगार मिल पा रहा था। • सेवा क्षेत्र: इसमें कार्यबल का 15-20% हिस्सा शामिल था। • क्षेत्रीय भिन्नता का विकास: तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी, बॉम्बे और बंगाल के कुछ हिस्सों में कृषि क्षेत्र पर श्रमबल की निर्भरता में गिरावट देखी गई, साथ ही विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में वृद्धि हुई। • उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में एक ही समय के दौरान कृषि में कार्यबल की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई।

आधारिक संरचना	• रेलवे, बंदरगाह, जल परिवहन, डाक और तार जैसी सुविधाओं हेतु बुनियादी ढाँचे का विकास हुआ।
	• सड़कें: ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत में निर्मित सड़कें आधुनिक परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं थी अर्थात नई सड़कों का निर्माण किया गया।
	  ○ उद्देश्य: भारत के भीतर सेना को संगठित करने और ग्रामीण इलाकों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या बंदरगाह तक पहुँचाने के लिए इन्हें दूर इंग्लैंड या अन्य आकर्षक विदेशी गंतव्यों में भेजने के लिए।
	• रेलवे: अंग्रेजों द्वारा 1850 में भारत में शरू की गई और इसे उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है।
	  ○ भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:
	  ○ इसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने और भौगोलिक और सांस्कृतिक बाधाओं को कम में सक्षम बनाया।
	  ○ इसने भारतीय कृषि के व्यावसायीकरण को बढ़ावा दिया जिसने भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की आत्मनिर्भरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।
	  ○ भारत के निर्यात की मात्रा में निस्संदेह विस्तार हुआ लेकिन इसका लाभ शायद ही कभी भारतीय लोगों को मिला हो।
	  ○ रेलवे की शुरुआत के कारण भारतीय लोगों को जो सामाजिक लाभ मिला, वह देश के भारी आर्थिक नुकसान से कहीं अधिक था।
	• अंतर्देशीय व्यापार और समुद्री मार्ग

	○ अंग्रेजों के ये उपाय संतोषजनक नहीं थे। ○ अंतर्देशीय जलमार्ग भी अलाभकारी साबित हुए जैसे उड़ीसा तट पर तटवर्ती नहर के मामले में। • टेलीग्राफ सिस्टम: भारत में विकसित टेलीग्राफ की महंगी प्रणाली की शुरूआत ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य की पूर्ति की। • डाक सेवाएँ : उपयोगी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के बावजूद अपर्याप्त बनी रहीं।

स्वतंत्रता के बाद की अर्थव्यवस्था

1950	• आर्थिक विकास की एक विशेष रणनीति को अपनाना। ○ तेजी से औद्योगीकरण: केंद्र द्वारा तैयार पंचवर्षीय योजना को लागू करना। ○ इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में संसाधन जुटाना और उन्हें बड़े औद्योगिक राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के निर्माण में निवेश करना निहित था। • चुने गए उद्योग: स्टील, रसायन, मशीन और उपकरण, इंजन, बिजली। • सार्वजनिक उद्यमों के निर्माण के लिए निवेश का निर्देश दिया गया। • लक्ष्य: सार्वजनिक स्वामित्व के तहत उत्पादक संसाधनों के एक बड़े हिस्से को लाने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग करके "समाज के समाजवादी पैटर्न" की स्थापना करना। • स्वतंत्र भारत में नियोजित और मिश्रित अर्थव्यवस्था थी।

नियोजित और मिश्रित अर्थव्यवस्था

योजनाबद्ध या समाजवादी अर्थव्यवस्था	मिश्रित आर्थिक प्रणाली
• एक आर्थिक प्रणाली जहाँ सरकार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करती है। • कभी-कभी इसे कमांड इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है। • सरकार फैसला करती है : ○ किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है, ○ उत्पादन और वितरण विधि, ○ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें • सरकार : केंद्रीय योजनाकार, नियामक और नियंत्रक। • उदाहरण : उत्तर कोरिया, ईरान, लीबिया और क्यूबा। • चीन में एक कमांड अर्थव्यवस्था थी। ○ साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों आदर्शों वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ने से पहले।	• कमांड और फ्री-मार्केट सिस्टम दोनों की विशेषताएँ। • आंशिक रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित और आंशिक रूप से ही मांग और आपूर्ति की शक्तियों पर आधारित। • दुनिया की अधिकांश महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएँ अब मिश्रित अर्थव्यवस्थाएँ हैं, ○ समाजवाद और पूंजीवाद के संयोजन के तहत संचालित, ○ राजकोषीय या मौद्रिक नीतियों का उपयोग ○ आर्थिक मंदी के दौरान विकास को प्रोत्साहित करने के लिए • मिश्रित आर्थिक प्रणाली में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र निहित हैं। • एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में सीमित सरकारी विनियमन।

2
CHAPTER

अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत

सूक्ष्म और स्थूल अर्थव्यवस्था

सूक्ष्म अर्थव्यवस्था	स्थूल अर्थव्यवस्था
• व्यक्तिगत और व्यावसायिक निर्णयों का अध्ययन किया जाता है। माँग और आपूर्ति, साथ ही अन्य कारक जो मूल्य स्तरों को प्रभावित करते हैं। • संभावित निवेशकों द्वारा निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। • एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को दर्शाता है। • यह भविष्यवाणी भी करता है कि भविष्य में किन वस्तुओं और सेवाओं की अत्यधिक माँग होगी। • प्रोफेसर राग्नार फ्रिस्क ने सूक्ष्मअर्थशास्त्र शब्द दिया।	• इस बात का अध्ययन करता है कि देश और सरकारें व्यावसायिक निर्णय कैसे लेते हैं। • अर्थव्यवस्था की दिशा और प्रकृति को समझने के लिए ऊपर से नीचे तक पूरी खोज करती है। • आर्थिक और राजकोषीय नीति का विश्लेषण करने की एक विधि है। • सुनिश्चित करती है कि देश के आर्थिक संसाधनों का उपयोग उनकी पूरी क्षमता के लिए किया जाता है या नहीं। • जॉन मेनार्ड कीन्स को आम तौर पर समकालीन समष्टि आर्थिक सिद्धांत का जनक माना जाता है।

आर्थिक प्रणाली

- संसाधनों को आवंटित करने और पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं को वितरित करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं और समन्वय तंत्र का समूह

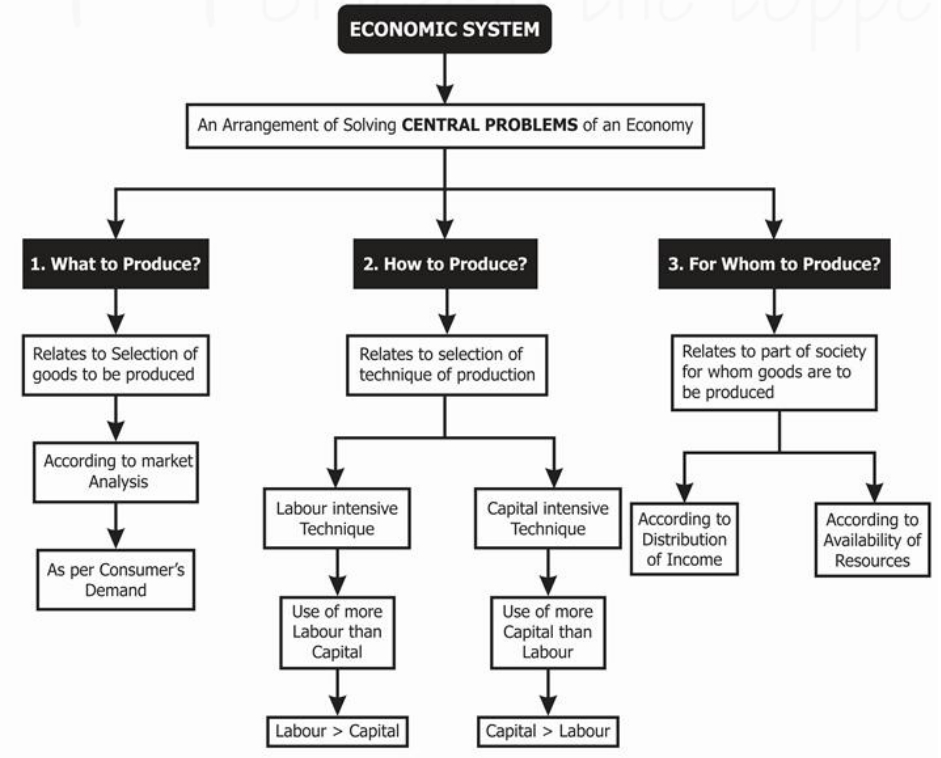

विभिन्न आर्थिक प्रणालियाँ

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था	• एक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न उत्पादों को व्यक्तियों के बीच वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। • उत्पादों और सेवाओं को खरीदने के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त धन होना चाहिए। • माँग के बावजूद क्रय शक्ति की कमी के कारण माल का उत्पादन नहीं हो सकता है।
समाजवादी अर्थव्यवस्था	• सरकार तय करती है कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पाद बनाया जाए। • व्यक्तिगत खरीददारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। • सिद्धांत रूप में समाजवाद के तहत साझा करना इस आधार पर होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए, न कि वह जो वहन कर सकता है। • समाजवादी शासन में कोई अलग संपत्ति नहीं।
मिश्रित अर्थव्यवस्था	• अर्थव्यवस्था कभी भी स्थायी रूप से राज्य के हस्तक्षेप या मुक्त बाजार की ओर नहीं झुकी बल्कि अर्थव्यवस्था की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार हमेशा राज्य और बाजार का संतुलित मिश्रण रही।

पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में अंतर

मापदंड	पूँजीवादी अर्थव्यवस्था	समाजवादी अर्थव्यवस्था	मिश्रित अर्थव्यवस्था
स्वामित्व	निजी	सार्वजनिक	सार्वजनिक और निजी दोनों
मूल्य निर्धारण	बाजार की ताकतों से	केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण द्वारा।	केंद्रीय योजना प्राधिकरण और बाजार शक्तियों द्वारा
उत्पादन का उद्देश्य	लाभ कमाना	सामाजिक कल्याण	निजी क्षेत्र में लाभ और सार्वजनिक क्षेत्र में कल्याण
सरकार की भूमिका	कोई भूमिका नहीं	पूर्ण नियंत्रण में	सार्वजनिक क्षेत्र में पूर्ण भूमिका और निजी क्षेत्र में सीमित
प्रतिस्पर्द्धा	मौजूद	कोई प्रतियोगिता नहीं	केवल निजी क्षेत्र में
आय वितरण	बहुत असमान	बिल्कुल बराबर	काफ़ी असमानताएँ मौजूद होती हैं

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र

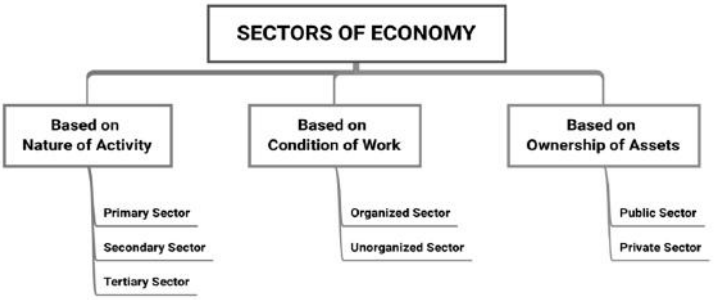

आर्थिक गतिविधि की प्रकृति पर आधारित

प्राथमिक क्षेत्र

- प्राकृतिक संसाधनों की निकासी या कच्चे माल के निर्माण में शामिल उद्योग।
- उदाहरण के लिए कृषि, मछली पकड़ना और खनन आदि।

द्वितीयक क्षेत्र

- उपयोगी वस्तुओं या पूर्ण वस्तुओं के उत्पादन में शामिल उद्योग
- जैसे: भारी और हल्के उद्योग (इस्पात, रसायन और ऑटोमोबाइल) (भोजन, परिधान, सौंदर्य प्रसाधन)।

तृतीयक क्षेत्र

- अन्य फर्मों या अंतिम उपभोक्ताओं को सेवाएँ प्रदान करना।
- उदाहरण: खुदरा, स्वास्थ्य देखभाल, और अन्य उद्योग

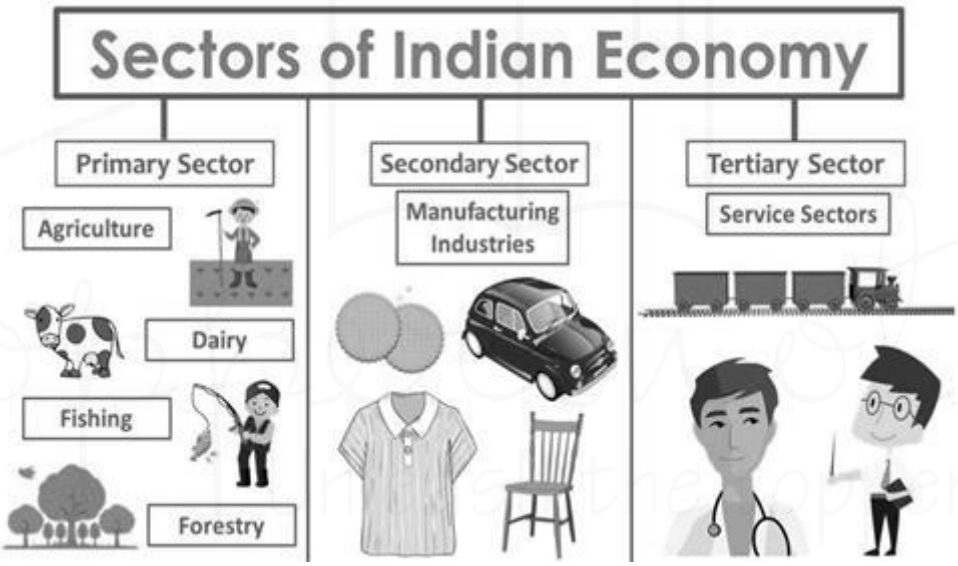

चतुर्थक क्षेत्र	• ज्ञान के निर्माण और प्रसार में निहित। • जैसे: अनुसंधान और विकास, शिक्षा आदि।
पंचम क्षेत्र	• किसी अर्थव्यवस्था में निर्णय लेने का उच्चतम स्तर।
गुलाबी कॉलर नौकरियाँ	• वह नौकरी जिसे पारंपरिक रूप से महिलाओं का काम या महिला-उन्मुख नौकरी माना जाता है। • अधिक पेशेवर प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। • जैसे: दाई, फूलवाला, डे केयर वर्कर, नर्स आदि।

कार्य की स्थिति पर आधारित

संगठित क्षेत्र

- उन उद्यमों या कार्यस्थलों को शामिल करता है जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं।
- सरकार द्वारा पंजीकृत और इसके नियमों और विनियमों का पालन करना होता है जो विभिन्न कानूनों जैसे फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम आदि में दिए गए हैं।

असंगठित क्षेत्र

- छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ जो सरकार के नियंत्रण में नहीं होती हैं। नियम और कानून हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता है।
- कम वेतन वाली नौकरियाँ, अक्सर नियमित नहीं होती हैं।
- रोजगार सुरक्षित नहीं है और नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है।
- असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की अनुसूची- II में उल्लिखित कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित किसी भी अधिनियम द्वारा कवर नहीं किया गया है।
- इसके अंतर्गत घर पर काम करने वाले कर्मचारी या स्वरोजगार करने वाले कर्मचारी या मजदूरी करने वाले कर्मचारी शामिल किए जाते हैं।

संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर

सार्वजनिक क्षेत्र

- स्वामित्व: सरकार के तहत।
- मुख्य रूप से सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के उद्देश्य से।
- जैसे: रेलवे, भारतीय डाक सेवाएँ, आदि।

निजी क्षेत्र

- स्वामित्व: निजी व्यक्तियों या कंपनियों के अधीन।
- उदाहरण: टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (टिस्को) या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) जैसी कम्पनियाँ निजी स्वामित्व वाली हैं।

सूर्योदय उद्योग

- वह औद्योगिक क्षेत्र जो अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन तेजी से उछाल का वादा करता है।
- उच्च विकास दर, उच्च स्तर के नवाचार और आम तौर पर इस क्षेत्र के बारे में बहुत सारी जन जागरूकता होती है और निवेशक इसकी दीर्घकालिक विकास संभावनाओं से आकर्षित होते हैं।
- जैसे:
    - सूचना प्रौद्योगिकी
    - दूरसंचार क्षेत्र
    - स्वास्थ्य सेवा
    - आधारभूत संरचना क्षेत्र
    - खुदरा क्षेत्र
    - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
    - मत्स्य पालन

माँग आपूर्ति प्रबंधन

माँग वक्र: यह वस्तु की कीमत और उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय सीमा में उस वस्तु को खरीद पाने की क्षमता के मध्य सम्बन्ध को प्रदर्शित करता है।यह वक्र वरीयताओं, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतों, अपेक्षाओं और खरीदारों की संख्या पर निर्भर करता है।

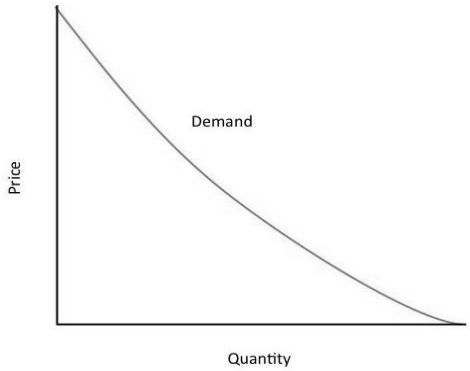

माँग के निर्धारक

- अच्छी कीमत
- क्रेता द्वारा उत्पाद की वरीयता या इच्छा का स्तर
- क्रेता की आय
- संबंधित उत्पादों की कीमतें :
  - स्थानापन्न उत्पाद (खरीदार की राय में उत्पाद के साथ सीधे प्रतिस्पर्द्धा; जैसे चाय और कॉफी)
  - पूरक उत्पाद (खरीदार की राय में वस्तु के साथ प्रयुक्त; जैसे कार और पेट्रोल)
- भविष्य की अपेक्षाएँ
  क्रेता की अपेक्षित आय।
  वस्तु का अपेक्षित मूल्य।

माँग में कमी करने वाले परिवर्तन

- स्थानापन्न वस्तु की घटी हुई कीमत
- पूरक वस्तु की बढ़ी हुई कीमत
- सामान्य वस्तु है तो आय में कमी
- आय में वृद्धि अगर अवर वस्तु है।

माँग की लोच

- मूल्य चर (P) में परिवर्तन के लिए मात्रा चर (Q) की संवेदनशीलता का एक उपाय
- लोच का अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण है कि राजस्व कैसे भिन्न होगा क्योंकि यह इस मुद्दे का उत्तर देता है कि मूल्य में 1% परिवर्तन के लिए प्रतिशत के संदर्भ में मात्रा कितनी बदलेगी।
- बेलोचदार मांग वक्र अधिक है क्योंकि P में पर्याप्त परिवर्तन भी Q में थोड़ा परिवर्तन उत्पन्न करता है।
- जैसे: खाद्यान्न: अगर कीमत बहुत बढ़ जाती है, तो भी लोग अपनी खपत कम नहीं करेंगे; और अगर P गिरता है, तो लोग अपनी खपत नहीं बढ़ाएंगे।

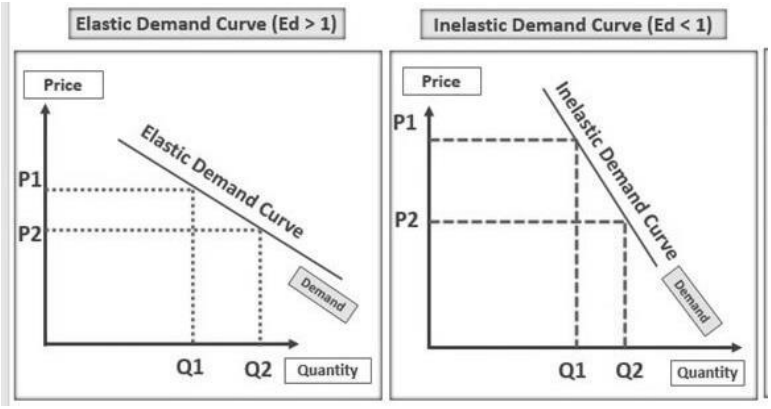

आपूर्ति क्या है?

- एक वस्तु की वह मात्रा जो एक कंपनी एक निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार होती है।
- 'आपूर्ति वक्र' का पालन किया जाता है। कीमत जितनी अधिक होगी, कंपनी को उतना ही अधिक बेचने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

वस्तु की आपूर्ति बढ़ेगी:

- लाभ = कुल राजस्व - कुल लागत
- राजस्व = उत्पादन की बिक्री के माध्यम से प्राप्त धन = मूल्य (पी) x मात्रा (क्यू)
- यदि अन्य सभी कारक स्थिर रहते हैं, तो उच्च मूल्य के परिणामस्वरूप लाभ होगा।
- माँग का नियम: जैसे-जैसे कीमत बढ़ती है, अनुरोधित मात्रा (Qd) घटती जाती है।
- आपूर्ति का नियम: जैसे-जैसे कीमत बढ़ती है, वैसे-वैसे प्रदान की गई मात्रा भी होती है (Qs)

आपूर्ति के निर्धारक

कर	• जैसे-जैसे कर बढ़ता है, आपूर्ति गिरती है और आपूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। • विनिर्माण लागत और लेवी में वृद्धि का समान प्रभाव पड़ेगा। • 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सरकार ने आपूर्ति बढ़ाने के लिए करों में कटौती की। • इसके परिणामस्वरूप आपूर्ति वक्र दायीं ओर खिसक गया।
उत्पादन लागत	• यदि उत्पादन की लागत बढ़ती है, तो आपूर्ति भी बढ़ती है। • आपूर्ति वक्र में बदलाव: जैसे-जैसे विनिर्माण लागत बढ़ती है, प्रदान की गई राशि कम हो जाती है और आपूर्ति वक्र बाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। • जब उत्पादन की लागत गिरती है, तो उत्पादित मात्रा में वृद्धि होती है। • आपूर्ति वक्र दाईं ओर तिरछा होगा।
कंपनी के लक्ष्य	• लाभ हमेशा किसी कंपनी का मुख्य लक्ष्य नहीं होता है। • इसका उद्देश्य बिक्री बढ़ाना या सामाजिक कल्याण में सुधार करना हो सकता है। • इस परिदृश्य में आपूर्ति बढ़ने पर आपूर्ति वक्र दाईं ओर झुकता है। • अच्छी बारिश से भी आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है।

आपूर्ति की लोच

"कीमत में बदलाव के लिए आपूर्ति की गई मात्रा की प्रतिक्रिया"

- उच्च लोच: यदि परिवर्तन तीव्र है
- लोच (एस): (आपूर्ति की मात्रा में% परिवर्तन) / (कीमत में% परिवर्तन)
- यदि Es>1: आपूर्ति लोचदार है
- यदि Es<1: आपूर्ति बेलोचदार है

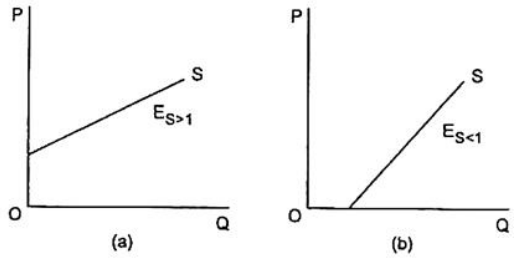

आपूर्ति की लोच के निर्धारक

- समग्र निर्धारक विकल्प है: फर्म के पास जितना अधिक विकल्प, उतना अधिक लोच
  - उदाहरण के लिए जल्दी खराब होने वाली वस्तु की मात्रा: फर्म के पास स्टोर करने का कोई विकल्प है/विकल्प नहीं है; किसी भी कीमत पर बेचना होगा।
  - कृषि वस्तुओं के लिए: बेलोचदार आपूर्ति।